स्वास्थ्यः नवीनतम प्रामाणिक जानकारी ज़रूरी

भारत डोगरा

स्वास्थ्य नियोजन विशेषज्ञ व स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिंतित हैं कि स्वास्थ्य सम्बंधी प्रमाणिक आंकड़े व जानकारी मिलने में देरी के कारण विभिन्न प्रयासों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है व भावी नियोजन में भी कठिनाइयां आ रही हैं।

इसकी एक मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (एन.एफ.एच.एस.) के परिणाम मिलने में देरी हुई है। इसके अगले दौर का फील्ड-वर्क वर्ष 2010 में आरंभ हो जाना था पर एक अनावश्यक विवाद के कारण यह टलता गया व अब बहुत देरी से यह वर्ष 2014 में हो रहा है। इस कारण स्वास्थ्य, पोषण व मृत्यु दर सम्बंधी जानकारी मिलने में देरी हो रही है।

कुछ वर्ष पहले तक सरकारी स्तर पर भी इस बारे में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही थी कि स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचकों में देश पिछड़ रहा है और सहस्त्राब्दी लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन लग रहा है। विशेषकर मृत्यु दर, बाल व शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर के संदर्भ में आम तौर पर लग रहा था कि देश की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

इस चिंताजनक स्थिति के समाधान के लिए कई विशेषज्ञों, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जैसे, स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि, मुनाफे की प्रवृत्ति पर रोक, तर्कसंगत दवा व वैक्सीन नीति, गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों में ज़रूरी सेवाओं व साज़-सामान सुनिश्चित करना तथा उचित पोषण के साथ स्वच्छ पेयजल व अन्य बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इन महत्वपूर्ण मामलों में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। आश्चर्य है कि ऐसी प्रगति के बिना ही स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचकों, विशेषकर बाल व मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी के दावे किए गए हैं।

यदि बाल व मातृ मृत्यु दर में वास्तव में इतनी कमी आई है तो यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, पर सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों व जिस तरह बाल कुपोषण की स्थिति है वह बहुत चिंताजनक बनी हुई है, उससे यह उपलब्धि संदिग्ध लगती है। अतः यह ज़रूरी है कि पंचायतों और प्रखंडों के स्तर पर सघन अध्ययन कर इन उपलब्धियों की प्रामाणिकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इस बारे में सही जानकारी सामने आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही जानकारी के आधार पर ही आगे के लिए उचित नीतियां बन सकेंगी और उचित नियोजन हो सकेगा।

इस बारे में चिंता की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि हाल के समय में प्रामाणिक आंकड़े एकत्र करने वाले कर्मचारियों में, विशेषकर ज़िला स्तर, पर कमी आई है। ज़िला सांख्यिकी कार्यालयों की क्षमता पहले से कम हुई है। दूसरी ओर दबाव है कि उच्च प्राथमिकता वाले सरकारी कार्यक्रमों में प्रतिकूल आंकड़े सामने न आएं। अतः यह चिंता बढ़ रही है कि शायद कागज़ी स्तर पर नज़र आने वाली बड़ी-बड़ी उपलब्धियां वास्तविकता से मेल न खाती हों। मलेरिया, तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में यह व्यापक चिंता है कि इनसे पीड़ित व्यक्तियों व विशेषकर इनसे होने वाली मौतों की संख्या काफी कम बताई जा रही है।

वास्तविक प्रगति के लिए एक आधार यह है कि पहले सही जानकारी उपलब्ध हो। अतः सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य उपलब्धियों व समस्याओं सम्बंधी सही व प्रामाणिक जानकारी ही लोगों के सामने रखे। ***(स्रोत फीचर्स)***